www.vidarbhakibaat.in

Post Reg. No. RNP/NPCITY /169 /2015-2017

प्रखर... मुखर... स्वर

विदर्भ की बात

● वर्ष 17 ● अंक 108 नागपुर, बुधवार, 15 मार्च 2017 ● पृष्ठ 8 ● मूल्य ₹ 2

चौथी बार मनोहर पर्रिकर ने संभाली गोवा के मुख्यमंत्री पद की कमान

पणजी

मनोहर पर्रिकर मंगलवार की शाम चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही एमजीपी के मनोहर अजगांवकर और निर्दलीय विधायक रोहन खुंटे ने भी गोवा सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। पर्रिकर को राज्यपाल ने सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। जिस वक्त पणजी में मनोहर पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उस समय गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर भी वहां पर मौजूद थे।

सिर्फ गोवा के विकास के लिए भाजपा को समर्थन

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पर्रिकर ने कहा कि गोवा में भाजपा को सरकार गठन करने के लिए जो समर्थन दिया गया है वह सिर्फ विकास के लिए है। कोई भी विधायक कांग्रेस को समर्थन नहीं करना चाहते थे।

उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि आपके पास सरकार बनाने का समर्थन था तो फिर आप राज्यपाल के पास क्यों नहीं गए। पर्रिकर ने कहा कि मैं मानता हूं कि गोवा में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन 22 विधायकों के एक साथ आने से इनका वोट शेयर पर्याप्त है। यह चुनाव के बाद का गठबंधन है।

कल तक साबित करना होगा बहुमत

हालांकि, कांग्रेस की तरफ से डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पर्रिकर को कल 16 मार्च तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस की उस याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने गवर्नर के फैसले पर सवाल उठाया था। इस याचिका में कहा गया था कि राज्य में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि भाजपा को सरकार बनाने के लिए कम नंबर होने के बाद भी आमंत्रित किया गया।

आदेश देने से पूर्व कांग्रेस को कोर्ट से फटकार भी खानी पड़ी। कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि जो बातें आप यहां कह रहे हैं उन्हें गोवा में गवर्नर के समक्ष क्यों नहीं कहा।

कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि आखिर सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस ने गवर्नर के समक्ष अपना दावा पेश क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांग्रेस द्वारा उठाए मुद्दों का एक ही हल है कि जल्दी से जल्दी फ़्लोर टेस्ट हो। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि आखिर कांग्रेस जितने विधायकों का दावा कर रही है वह कहां हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि नंबर वास्तव में सरकार बनाने के लिए काफी अहम हैं। कांग्रेस द्वारा यह याचिका गवर्नर के उस फैसले के खिलाफ की गई है, जिसमें राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने मनोहर पर्रिकर को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है।

शपथ लेने में चूक कर गए पर्रिकर, गडकरी ने टोका

रक्षामंत्री पद से इस्तीफा देकर गोवा के मुख्यमंत्री बने मनोहर पर्रिकर शपथ ग्रहण समारोह में एक चूक कर बैठे। दरअसल गलती से पर्रिकर ने मुख्यमंत्री पद की जगह मंत्री पद की शपथ ले ली। पर्रिकर जब शपथ ग्रहण कर लौटने लगे तो बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने उन्हें इस गलती से अवगत कराया।

इसके बाद पर्रिकर दोबारा राज्यपाल के पास लौटे और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

शत्रु संपत्ति कानून संशोधन बिल 2017 को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली

संसद ने शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी, जिसमें युद्ध के बाद पाकिस्तान एवं चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा ने शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2017 में राज्यसभा में किए गए संशोधनों को मंजूरी प्रदान करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। निचले सदन ने इस बारे में आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन द्वारा रखे गए शत्रु सम्पत्ति संशोधन और विधिमान्यकरण पांचवां अध्यादेश 2016 का निरुनुमोदन करने वाले संकल्प को अस्वीकार कर दिया।

जब किसी देश के साथ युद्ध होता है तो उसे शत्रु माना जाता है

इस बारे में हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी सरकार को अपने शत्रु राष्ट्र या उसके नागरिकों को संपत्ति रखने या व्यावयायिक हितों के लिए मंजूरी नहीं देनी चाहिए।

शत्रु संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए न कि शत्रु देशों के नागरिकों के उत्तराधिकारियों के पास। उन्होंने कहा कि जब किसी देश के साथ युद्ध होता है तो उसे शत्रु माना जाता है और शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2017 को 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

बिल पास नहीं कराने से होगा करोड़ों की संपत्ति का नुकसान

उपरोक्त युद्धों की पृष्ठभूमि में अपनी पुश्तैनी संपत्ति को छोड़कर शत्रु देश में चले जाने वाले पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों के संबंध में लाए गए इस विधेयक के संबंध में राजनाथ ने कहा कि इस विधेयक को पारित कराना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं होने से लाखों करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान होगा। सरकार द्वारा अध्यादेश का मार्ग अपनाये जाने पर विपक्ष की आलोचना पर गृहमंत्री ने कहा कि सरकार भी अध्यादेश का मार्ग नहीं अपनाना चाहती है। अत्यधिक जरूरत होने पर ही ऐसा किया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछली तिथि से प्रभावी होने का जो कुछ उल्लेख किया गया है, उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास नहीं भेजने के कुछ सदस्यों की आलोचना पर राजनाथ ने कहा कि इस बारे में व्यापक चर्चा हो चुकी है। इस विधेयक में कुछ शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है जिसमें 67वें के स्थान पर 68वें, 2016 के स्थान पर 2017 तथा किसी विधि के स्थान पर किन्ही विधियों आदि को प्रतिस्थापित किया गया है। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

सुप्रभात

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 5.9 तीव्रता का भूकंप

नई दिल्ली

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि मंगलवार को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.9 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप का केंद्र निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में था। सुबह 8 बजकर 21 मिनट पर आए भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं रहने के कारण सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई।

भारत में एक सुनामी केंद्र है जिससे राज्यों और पड़ोस के तटवर्ती इलाकों को सुनामी चेतावनी दी जाती है। भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। मंगलवार को ही अंडमान से पहले जम्मू एवं कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। राज्य के कठुआ में सुबह 5 बजकर 48 मिनट पर महसूस किए गए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 आंकी गई है।

सीबीआइ करेगी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर धोखाधड़ी की जांच

नई दिल्ली

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर नगद राशि का लालच देकर भरवाये जा रहे फर्जी फार्मों के मामले की जांच अब सीबीआइ करेगी। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच सीबीआइ को सौंप दी है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बार फिर साफ किया है कि सरकार की ओर से इस योजना के तहत किसी तरह के नगद प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं है। लोग किसी भी भ्रम में आकर अपनी निजी जानकारियां साझा न करें।

मालूम हो कि उत्तरप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार में लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नगद राशि दे रही है। नगद प्रोत्साहन राशि देने के नाम पर जिनके बेटियां हैं उन लोगों से फार्म भरवाये जा रहे हैं, जिसमे उनका पूरा ब्योरा भरवाया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तरप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और बिहार की राज्य सरकारों के समक्ष उठाया। यह योजना बालिकाओं के महत्व को समझाने, पीसी एंव पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू कराने को लेकर है। यह योजना सामाजिक व्यवस्था में लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने और समाज की पितृ सत्तात्मक सोच को बदलने के बारे में है। मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वे किसी भी तरह की धोखाधड़ी में न फंसे अपनी जानकारी साझा न करें।

मामले की गंभीरता और जनहित को देखते सरकार ने योजना में नगद राशि के प्रोत्साहन के नाम पर गलत तरीके से प्रारूप और फार्म भरवाये जाने की जांच सीबीआइ को सौंप दी है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने संभाला रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार

नई दिल्ली

मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री की नयी भूमिका संभालने के लिए रक्षामंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जेटली ने रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला।

इससे पहले 2014 में भी छह महीने तक उनके पास दोनों कार्यभार थे। सोमवार को राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी एक संदेश में कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर रक्षामंत्री के पद से मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर किया जाता है। इसमें कहा गया है, इसके साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री अरुण जेटली को उनके मौजूदा विभागों के अलावा रक्षा मंत्रालय की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा द्वारा गोवा में गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बाद पर्रिकर ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। भाजपा के नेतृत्व वाले मौजूदा एनडीए गठबंधन सरकार में यह दूसरा मौका है जब जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। मोदी कैबिनेट में वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक जेटली 26 मई 2014 से लेकर नौ नवंबर 2014 तक भी रक्षा मंत्रालय के प्रभारी रहे थे। इसके बाद पर्रिकर को गोवा से लाकर रक्षामंत्री बनाया गया था। रक्षामंत्री के रूप में पर्रिकर के कार्यकाल में रक्षा सौदों में अड़चनें दूर हुईं और खरीद प्रक्रिया सरल हुईं।

गोवा और मणिपुर में लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश - राहुल गांधी

नई दिल्ली

गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और भाजपा को 13 सीटें मिली हैं। इसके बाद भी भाजपा ने आगे बढ़कर राज्य में सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल से मुलाकात करके दावा पेश कर दिया और राज्यपाल ने भाजपा को सरकार बनाने का न्योता भी दे दिया। उसके खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की इस दलील को खारिज कर दिया कि मनोहर पर्रिकर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोका जाए, लेकिन गोवा के राज्यपाल द्वारा भाजपा को बहुमत साबित करने के लिए जो 15 दिनों का समय दिया था उसको घटाकर 16 मार्च का समय मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जब कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा गया तो उनका जवाब था कि पहले गाड़ी से बाहर निकलूंगा तो उसके बाद जवाब दूंगा।

धनबल के सामने लोकतंत्र नतमस्तक

गोवा और मणिपुर में भाजपा जो कुछ कर रही है वो सभी के सामने है।

भाजपा की इन्हीं नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में से तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन गोवा और मणिपुर में पैसे और शक्ति के बल पर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

भाजपा की जीत के पीछे कई वजहें

विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार पर राहुल गांधी ने कहा कि हम विपक्ष में हैं। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं हम भी सामना कर रहे हैं। उत्तरप्रदेश में हमें आशातीत सफलता नहीं मिली जिसे हम स्वीकार करते हैं। हमारी लड़ाई भाजपा की विचारधारा से है। भाजपा की शानदार जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो वो बधाई देते हैं, लेकिन भाजपा की जीत के पीछे तमाम वजहें थीं, जिनमें ध्रुवीकरण प्रमुख था।

कैप्टन की सरकार में सिद्धू को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

चंडीगढ़

पंजाब चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिलेगा कि नहीं इस पर संशय बरकरार है। मीडिया रिपोर्टों की मानें तो सिद्धू हॉकी के पूर्व कप्तान परगट सिंह और मनप्रीत सिंह बादल को अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मीडिया रिपोर्टों की मानें तो क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू के डिप्टी-सीएम बनाए जाने का प्रदेश के कई कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। नेताओं का कहना है कि हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को ही करना है।

सत्ताविरोधी लहर के कारण कांग्रेस ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीटों पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार अमरिंदर ने अपने मंत्री परिषद् का ब्यौरा साझा नहीं किया, लेकिन पार्टी के सूत्रों ने कहा कि सिद्धू सहित कई निर्वाचित विधायक, निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के रिश्तेदार मनप्रीत और रजिया सुल्ताना मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। पंजाब में दस वर्ष के बाद सत्ता में लौट रही कांग्रेस विभिन्न जाति, धर्म, क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व दे सकती है।

सूत्रों ने बताया कि माझा इलाके से मंत्री पद के लिए अन्य संभावितों में सुखजिंदर रंधावा (डेरा बाबा नानक), तृप्त सिंह राजिंदर बाजवा (फतेहगढ़ चूड़ियां) और ओ पी सोनी (अमृतसर मध्य) शामिल हैं। दोआबा के पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह (जालंधर कैंट), राणा गुरजीत सिंह (कपूरथला) और शाम सुंदर अरोड़ा (होशियारपुर) मंत्री पद के दावेदारों में शामिल हैं।

मणिपुर में भी सरकार बनाएगी भाजपा, राज्यपाल ने भेजा न्योता

आज होगा शपथ ग्रहण समारोह

नई दिल्ली

मणिपर में सियासी संकट हल होता दिख रहा है। मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया है। मणिपुर में आज बुधवार को भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कहा, मैंने जो फैसला किया है नियमों के मुताबिक लिया है। यह जरूरी नहीं है कि सबसे बड़ी पार्टी

को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। राज्यपाल ने कहा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी स्थिर सरकार दे सकती है यह देखना होता है। गौरतलब है कि मणिपुर में ओ इबोबी सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एन बीरेन सिंह को सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बीरेन सिंह राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उधर, एनपीएफ के चार विधायकों ने मणिपुर की राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार गठन के लिए भाजपा को समर्थन देने की बात कही। ■ शेष पृष्ठ 2 पर

चीन से युद्ध हुआ तो बॉर्डर तक नहीं जा पाएंगी बोफोर्स, हॉवित्जर्स - सीएजी

नई दिल्ली

क्या आप सोच सकते हैं कि चीन से लगने वाली सामरिक सड़कें मिलिट्री वाहनों (आर्टिलरी हॉवित्जर्स, बोफोर्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पिनाका और स्मर्च) का बोझ उठाने लायक नहीं हैं। संसद में पेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में 73 सड़कों में से 61 सड़कों के निर्माण के लिए कमजोर योजना, खराब कार्यान्वयन और वित्तीय अनियमितताओं की बात का खुलासा हुआ है। इन सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के पास है। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की

समिति ने दो साल पहले सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण मानते हुए जिन 73 सड़कों को निर्माण के लिए चुना था, उनमें से अब तक 22 से 23 को ही पूरी तरह तैयार किया जा सका है। इन सभी रूट्स का निर्माण सरकार की ओर से 2016 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

सीएजी ने संसद में पेश की रिपोर्ट

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रणनीतिक तौर पर संवेदनशील इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर ना होने या कमजोर ढांचे के चलते सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल क्षमता कमजोर होती है। रिपोर्ट के मुताबिक 61 सड़कों के निर्माण के लिए मंजूर किए गए 4,644 करोड़ रुपये में से 4,536 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 707 किलोमीटर लंबी 22 सड़कों का ही निर्माण किया जा सका है। चीन से लगती 4,057 किलोमीटर लंबी वास्तविक सीमा रेखा के पास भारत अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर कुछ हद तक विकसित कर पाया है। हालांकि इसके बाद भी जमीन पर इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं हो सका। सीएजी ने चीन से लगने वाली सामरिक सड़कों के निर्माण में समय रहते तुरंत कार्रवाई की बात कही है।